भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1620

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

पीएम ई-विद्या योजना के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा

†1620. **डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दिना पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-विद्या योजना के अंतर्गत छात्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की डिजिटल शिक्षा पहलों से महाराष्ट्र राज्य के कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में इन लाभों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना विकास हेतु सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने पीएम ई-विद्या संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को डिजिटल उपकरण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) पीएम ई-विद्या योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य डिजिटल संसाधन प्रदान किए गए हैं;

(च) शेष विद्यालयों को इस योजना से जोड़ने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) छात्रों के अधिगम परिणामों, विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता में पीएम ई-विद्या योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) (पैरा 4.23) में उल्लेख किया गया है कि कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सभी छात्रों द्वारा सीखा जाना चाहिए, जिसमें डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल सोच शामिल है, जिन्हें विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में **पीएम ई-विद्या** नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो शिक्षा तक बहु-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई-विद्या पहल को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है और एनसीईआरटी के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। इन पहलों के घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में भी अनुकूलित हैं और इसमें शामिल हैं:

- डीटीएच टीवी चैनल: इन चैनलों को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 9 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था।

  वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। एनसीईआरटी के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को चैनल आवंटित किए गए हैं और वे चालू हैं।

  इसके अलावा, 6 दिसंबर 2024 को, भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और आईएसएल में शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यापक पहुंच को व्यापक दर्शकों तक सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुरूप, माननीय शिक्षा मंत्री ने एक समर्पित पीएम ईविद्या डीटीएच चैनल (चैनल नंबर 31) के माध्यम से श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पहल शुरू की। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेज़ी) और एनसीईआरटी/एनआईओएस वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर सांकेतिक भाषा में विशेष ई-सामग्री तैयार की गई।

  ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा डीटीएच चैनलों और यूट्यूब पर प्रतिदिन डिजिटल साक्षरता पर एक घंटे की सामग्री प्रसारित की जाती है।

- दीक्षा राष्ट्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराता है (**एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म**) । दीक्षा पर कुल 560.09 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल हैं।

एनसीईआरटी दीक्षा मंच के माध्यम से निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिसका एक उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है, जिसका उपयोग छात्रों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। निष्ठा (प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई) भारतीय भाषाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल करता है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण-अधिगम में आईसीटी शामिल पाठ्यक्रमों में से एक है। यह उल्लेखनीय है कि सभी निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूल शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण - शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पर समर्पित पाठ्यक्रम मॉड्यूल हैं। 63 लाख शिक्षकों ने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

महत्वपूर्ण आलोचनात्मक विचार कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को महत्व देने के लिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल बनाया गया है। देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल लैब्स पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

पीएम ईविद्या के तहत, महाराष्ट्र राज्य को पाँच डीटीएच चैनल सौंपे गए हैं जो मराठी भाषा में सफलतापूर्वक सामग्री चला रहे हैं। साथ ही, महाराष्ट्र के 20 मास्टर ट्रेनर्स को पीएम ईविद्या 200 डीटीएच चैनलों के लिए चरणों में आयोजित विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। लगभग 1,08,995 पंजीकृत उपयोगकर्ता (छात्र) सामग्री का उपभोग कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दीक्षा पर 22,641 संसाधन अपलोड किए गए हैं। महाराष्ट्र के 4,53,220 शिक्षकों को दीक्षा के तहत ई-सामग्री विकास सहित विभिन्न आईसीटी घटकों पर प्रशिक्षित किया गया है।

ग) समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईसीटी लैब्स के अंतर्गत 62,581.60 लाख रुपये और स्मार्ट क्लासरूम के अंतर्गत 60,385.2 लाख रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा घटक के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को 33,760 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

घ) सरकार समग्र शिक्षा के तहत छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव के आधार पर शिक्षकों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराती है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 15.72 लाख शिक्षकों को शिक्षण संसाधन पैकेज के रूप में डिजिटल डिवाइस दी जा चुकी है।

ङ) यूडाइज़+ 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, 65,064 सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों में से 35,349 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। 1,08,195 स्कूलों में से **10,463** स्कूलों में आईसीटी लैब उपलब्ध हैं, **3,292** स्कूलों में स्मार्ट क्लास उपलब्ध हैं और **18,436** स्कूलों में डीटीएच कनेक्टिविटी है।

च) केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।

छ) इस प्रकार, डिजिटल साक्षरता सहित छात्र अधिगम परिणामों पर पीएम ई-विद्या योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि पीएम ई-विद्या स्कूल शिक्षण के लिए एक पूरक तंत्र है। तथापि, छात्रों के अधिगम परिणामों का मूल्यांकन समय-समय पर किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) द्वारा 4 दिसंबर 2024 को सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में चरण-विशिष्ट दक्षताओं की उपलब्धि को समझने के लिए एक आधारभूत अध्ययन है। यह देश भर के स्कूलों के पूरे आयामों को कवर करता है।

****